चीनी मिलों ने इस साल पेराई न करने की चेतावनी दी

[जयश्री भोसले | पुणे]

उत्तर प्रदेश शुगर इंडस्ट्री ने चीनी की कम कीमतों को देखते हुए प्रदेश सरकार को बता दिया है कि उन्हें इसमें कोई भविष्य दिखाई नहीं देता है और 2018-19 के सत्र में ऑपरेशन के लिए सक्षम नहीं हैं। शुगर इंडस्ट्री 2018-19 सत्र से संबंधित फील्ड सर्वे और दूसरी गतिविधियों में भी हिस्सा नहीं लेगी। उत्तर प्रदेश के चीनी उत्पादन में 36 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई है। यह पिछले साल 87.73 लाख टन था, जो बढ़कर 119.12 लाख टन तक पहुंच गया है। इसमें अभी भी बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश के शुगर प्रॉडक्शन में 2018-19 के पेराई सत्र के दौरान भी बढ़ने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन (UPSMA) ने 2018-19 पेराई सत्र से जुड़ी गतिविधियों में भाग नहीं लेने के बारे में प्रदेश सरकार को बता दिया है। इसने तीन साल पहले भी इसी तरह की चेतावनी दी थी, जब प्रदेश सरकार ने गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी की थी।

- **यूपी शुगर** मिल्स एसोसिएशन ने 2018-19 पेराई सत्र में भाग नहीं लेने के बारे में प्रदेश सरकार को बता दिया है
- **यूपी के** चीनी उत्पादन में 36 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई है। यह पिछले साल 87.73 लाख टन था, जो बढ़कर 119.12 लाख टन तक पहुंच गया है

सरकार को लिखे पत्र में एसोसिएशन ने बताया, 'हमारे पास आगे का कोई रोडमैप नहीं है। अगले सत्र के लिए गन्ने की कीमतें भी तय नहीं हैं। चीनी के दाम भी निचले स्तर पर बने हुए हैं। इसलिए हमें इसमें कोई भविष्य नहीं दिख रहा। मौजूदा हालात में लग रहा है कि हम अगले सत्र में पेराई करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए अगले सत्र से संबंधित फील्ड सर्वे और दूसरी गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं।' खराब सीजन का सामना कर रही एसोसिएशन ने सरकार से इंडस्ट्री से राहत की मांग की है, जिससे एक अच्छा सत्र शुरू किया जा सके।

प्रदेश के प्राइवेट शुगर इंडस्ट्री से जुड़े एक पदाधिकारी ने बताया, 'समस्या का सबसे बड़ा कारण है कि गन्ने और चीनी की कीमतों में कोई तालमेल नहीं है। चीनी की मौजूदा कीमत 26 रुपये प्रति किलो है, जो लगातार गिर रही है। इंडस्ट्री के आमदनी के स्रोत कम हो चुके हैं। गन्ना किसानों का भुगतान करने के लिए पैसा भी नहीं है।' पदाधिकारी ने कहा कि यह काफी दुखद है कि राज्य सरकार ने हालात का जायजा नहीं लिया है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का बकाया बढ़कर 12,500 करोड़ रुपये हो गया है। पदाधिकारी ने कहा, 'हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि हम इस बकाए को कैसे खत्म करें।'

ET (Hindi)
5/6/2018